



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आषाढ़ 1939 (श0)
(सं0 पटना 533) पटना, बुधवार, 28 जून 2017

सं0 08/आरोप-01-35/2014, सां0 प्र0-2762
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
7 मार्च 2017

श्री उमेश कुमार वर्मा, बि० प्र० से०, कोटि क्रमांक-144/08, 23/11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अररिया (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध हाई मास्ट लाईट के अधिष्ठापन में अनियमितता बरतने से संबंधित जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक-1431, दिनांक 28.10.2014 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों (प्रपत्र 'क' सहित) पर ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-209386, दिनांक 21.11.2014 प्राप्त हुआ। जिसमें श्री वर्मा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' गठित करते हुए श्री वर्मा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु संकल्प ज्ञापांक-17963, दिनांक 29.12.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। कालान्तर में श्री वर्मा के सेवानिवृत्ति (दिनांक 31.12.2014) के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-412, दिनांक 09.01.2015 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) के तहत सम्पूरित किया गया। इसके उपरान्त ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप, प्रपत्र 'क' में निहित गबन के मामले में कतिपय बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक-914, दिनांक 20.01.2015 द्वारा जिला पदाधिकारी, अररिया से पूरक आरोप, प्रपत्र 'क' की माँग की गयी। जिसके अनुपालन में जिला पदाधिकारी, अररिया का प्रतिवेदन (पत्रांक-151, दिनांक 07.02.2015) ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-994 (अनु०) दिनांक 07.04.2015 द्वारा प्राप्त हुआ। आरोपों की समेकित जाँच हेतु जिला पदाधिकारी, अररिया के उक्त प्रतिवेदन (पत्रांक-151, दिनांक 07.02.2015) की छायाप्रति विभागीय पत्रांक-6233, दिनांक 28.04.2015 द्वारा संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी गयी।

विभागीय जाँच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-44 (अनु०) दिनांक 29.01.2016 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। विभागीय पत्रांक-2183, दिनांक 11.02.2016 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोपों पर श्री वर्मा से लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण पृच्छा) माँगा गया। इस क्रम में श्री वर्मा ने अपना स्पष्टीकरण (दिनांक 29.02.2016 एवं दिनांक 28.03.2016) समर्पित किया।

विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क', संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री वर्मा से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत राजस्व की क्षति के प्रमाणित आरोपों के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-13611, दिनांक 05.10.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) के तहत उनके पेंशन से 75 प्रतिशत की कटौती का आदेश पारित किया गया।

2. श्री वर्मा ने उक्त पेंशन कटौती के विरुद्ध अपना पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दिनांक 02.11.2016 समर्पित किया। जिसमें उन्होंने स्वयं के विरुद्ध गठित/प्रमाणित आरोपों का प्रतिकार करते हुए यह उल्लेख किया है कि जाँच पदाधिकारी ने हाई मास्ट लाईट अधिष्ठापन से संबंधित प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के सत्यता की जाँच किये बिना ही उनके विरुद्ध दोष प्रमाणित बता दिया। विभागीय कार्यवाही में उनके द्वारा रखे गये पक्ष के आलोक में गवाही नहीं ली गयी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पेंशन से 75 प्रतिशत स्थायी कटौती होने से उनका जीवन-यापन अत्यन्त कठिन हो जायेगा। इन सब के आधार पर आरोपी पदाधिकारी ने स्वयं को आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया है।

3. आरोप, प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन, श्री वर्मा के लिखित अभिकथन एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समेकित समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि उनके कार्यकाल में स्वीकृत 36 हाई मास्ट लाईट में से एक भी न तो पूर्णतः अधिष्ठापित हुई और न ही क्रियाशील हुई। जबकि संबंधित संवेदक/एजेन्सी को बिना बैंक गारन्टी लिये ही 1.58 करोड़ रुपये भुगतान भी कर दिया गया। निःसंदेह इस कृत्य से सरकारी राशि का अपव्यय हुआ। संवेदक/एजेन्सी का गलत पता संधारित रहने के कारण उनके विरुद्ध प्राथमिकी (485/09, दिनांक 09.10.2009) एवं सर्टिफिकेट वाद दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी/राशि वसूली की कार्रवाई नहीं हो सकी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा भी उक्त अनियमितता का संज्ञान लिया गया। इस प्रकार बड़े पैमाने पर राजस्व की क्षति का आरोप प्रमाणित पाया गया। परन्तु अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में श्री वर्मा ने उक्त प्रमाणित आरोपों के बचाव में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया।

4. वर्णित स्थिति में श्री वर्मा के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन, दिनांक 02.11.2016 को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-13611, दिनांक 05.10.2016 द्वारा पेंशन से 75 प्रतिशत कटौती संबंधी पारित आदेश को यथावत रखा जाता है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
 सरकार के अवर सचिव।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
बिहार गजट (असाधारण) 533-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>